



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 12-2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JANUARY 22, 2021 (MAGHA 2, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 2021

**संख्या 03/जीएसटी-2.**— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।  
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 22 दिसंबर, 2020 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है), में, नियम 8 में, उपनियम (4क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, तथा अधिसूचित की जाने वाली तिथि से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(4क) उपनियम (4) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के पश्चात्, आवेदक, जहां आवेदक कोई व्यक्ति है अथवा जहां आवेदक कोई व्यक्ति नहीं है, वहा धारा 25 की उपधारा (6ग) के अधीन यथा अधिसूचित आवेदक के संबंध में आने वाले ऐसे व्यक्तियों का—

- (क) बायोमैट्रिक आधारित आधार अभिप्रमाणन और फोटोग्राफ लिया जाएगा, यदि उसे धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन छूट प्राप्त न हो और यदि उसने अपने आधार संख्या के अभिप्रमाणन का विकल्प दिया हो तो; या
  - (ख) यथा अधिसूचित बायोमैट्रिक सूचना, फोटोग्राफ लिया जाएगा और ऐसे अन्य के वाई सी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, यदि उसे धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन छूट प्राप्त न हो और यदि उसने आधार के अभिप्रमाणन का विकल्प नहीं चुना है, और साथ ही प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रतियों का, इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र में, सत्यापन किया जाएगा और ऐसे आवेदन को तभी पूरा माना जाएगा जब इस उपनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया पूरी हो जाती है।"
- उक्त नियमों में, नियम 9 में,—
    - (क) उपनियम (1) में —
      - (i) "आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से" शब्दों के पश्चात्, "तीन" शब्द के स्थान पर, "सात" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
      - (ii) विद्यमान परंतुकों के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु जहां—

- (क) धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या के अभिप्रमाणन में असफल रहता है या आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन नहीं करता है; या
- (ख) समुचित अधिकारी, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी जो राज्य कर उप आयुक्त से नीचे की पदवी का न हो, के अनुमोदन से कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन करवाया जाना उचित समझता है, तो, नियम 25 के अधीन उपबन्धित रीति में, उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में कारबार के स्थान के भौतिक सत्यापन तथा ऐसे दस्तावेज जो समुचित अधिकारी उचित समझे के सत्यापन के पश्चात्, आवेदन के प्रस्तुत करने के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।”;
- (ख) उपनियम (2) में,
  - (i) “तीन” शब्द के स्थान पर, “सात” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
  - (ii) विद्यमान परंतुकों के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु जहां—

- (क) धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न, कोई व्यक्ति नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अभिप्रमाणन करवाने में असफल रहता है या आधार संख्या के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन नहीं करता है; या
- (ख) समुचित अधिकारी, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी जो राज्य कर उपआयुक्त से नीचे की पदवी का न हो, के अनुमोदन से, कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन करवाया जाना उचित समझता है, तो, आवेदन के प्रस्तुत करने की तिथि से तीस दिनों के अपश्चात् प्ररूप जीएसटी आरईजी-03 में नोटिस जारी किया जा सकता है।”;
- (ग) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
- “(5) यदि समुचित अधिकारी,—
  - (क) आवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर उन मामलों में जहां व्यक्ति उपनियम (1) के परंतुक के अधीन नहीं आता है;
  - (ख) आवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर उन मामलों में जहां व्यक्ति उपनियम (1) के परंतुक के अधीन आता है; या
  - (ग) उपनियम (2) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर,
 कोई कार्रवाई करने में असफल रहता है, तो रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित किया गया समझा जाएगा।”।

4. उक्त नियमों में, नियम 21 में,—

- (1) खंड (ख) में, “माल या सेवाओं” शब्दों के पश्चात् “या दोनों” शब्दों को रखा जाएगा;
- (2) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—
  - “(ङ) अधिनियम की धारा 16 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों की उल्लंघना में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है; या
  - (च) एक या एक से अधिक कर अवधियों के लिए धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में आवक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करता है जो उक्त कर अवधियों के लिए धारा 39 के अधीन उसकी वैध विवरणी में उसके द्वारा घोषित किए गए जावक प्रदायों से अधिक है; या
  - (छ) नियम 86ख के उपबन्धों का उल्लंघन करता है।”।

5. उक्त नियमों में, नियम 21क में, —

- (क) उपनियम (2) में, “उक्त व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;
- (ख) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
  - “(2क) जहां, धारा 39 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों की तुलना
  - (क) प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे; या
  - (ख) प्ररूप जीएसटीआर-1 में उसके आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरों के आधार पर निष्कर्षित आवक प्रदायों के ब्यौरे,

या ऐसे अन्य विशलेषण, जो परिषद् की सिफारिशों पर किए जा सकते हैं, करने पर यह पता चलता हो कि ऐसे महत्वपूर्ण अंतर या विसंगतियां हैं जो अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन को

- दर्शाता है, जिससे उक्त व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता हो, तो उसके रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर दिया जाएगा और उक्त व्यक्ति को, उक्त अंतर और विसंगतियों को दर्शाते हुए, सामान्य पोर्टल पर, इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 में या रजिस्ट्रीकरण के समय दिए गए ई-मेल पते, या समय-समय पर यथा संशोधित पते पर, संसूचना भेजते हुए और उसे तीस दिन की अवधि के भीतर यह स्पष्ट करते हुए कि उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द क्यों न किया जाए, सूचित किया जाएगा।”;
- (ग) उपनियम (3) में, “या उपनियम (2)” शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात् “या उपनियम (2क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
- (घ) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-  
 “(3क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उपनियम (2) या उपनियम (2क) के अधीन निलंबित कर दिया गया हो, उसके रजिस्ट्रीकरण के निलंबित रहने के अवधि के दौरान, धारा 54 के अधीन कोई भी प्रतिदाय प्रदान नहीं किया जाएगा।”;
- (ङ) उपनियम (4) में, —  
 (i) “या उपनियम (2)” शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, “या उपनियम (2क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;  
 (ii) अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा  
 (iii) निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-  
 “परंतु इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलंबन को समुचित अधिकारी द्वारा रद्दकरण के लिए कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय प्रतिसंहरित किया जा सकता है, यदि वह उचित समझे।”।
6. उक्त नियमों में, नियम 22 में,—  
 (क) उपनियम (3) में, “उपनियम (1) के अधीन जारी किया गया कारण बताओ के” शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, “या नियम 21क के उपनियम (2क) के अधीन” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;  
 (ख) उपनियम (4) में, “उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युत्तर” शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, “या नियम 21क के उपनियम (2क) के अधीन जारी किए गए नोटिस के प्रत्युत्तर में” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
7. उक्त नियमों में, नियम 36 में, उपनियम (4) में, प्रथम जनवरी, 2021 से, —  
 (क) “अपलोड” शब्द, जहां कहीं भी आए के स्थान पर, “प्रस्तुत” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;  
 (ख) “धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा” शब्द, अंक और कोष्ठक जहां कहीं भी आए के पश्चात्, “प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा की उपयोग करते हुए” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;  
 (ग) “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “पाँच प्रतिशत” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
8. उक्त नियमों में, नियम 59 में, उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा तथा दिसंबर, 2020 के इकतीसवें दिन तक की अवधि के लिए रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-  
 “(5) इस नियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी,—  
 (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में मालों या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उसने पूर्ववर्ती दो मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3 बी में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है;  
 (ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसके लिए धारा 39 के उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है, प्ररूप जीएसटीआर-1 में धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने अथवा बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उसने पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3 बी में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है;  
 (ग) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो नियम 86ख के अधीन अपने इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में उपलब्ध राशि का अपने कर दायित्व के निर्वहन का, ऐसे कर दायित्व के निन्धानवे प्रतिशत से अधिक उपयोग करने से प्रतिबंधित है, को प्ररूप जीएसटीआर-1 में धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों को ब्यौरे प्रस्तुत करने अथवा बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उसने पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

9. उक्त नियमों में, नियम 86क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा तथा प्रथम जनवरी, 2021 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

"86ख. इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि के उपयोग पर प्रतिबंध:- इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उन मामलों में ऐसे दायित्व के निन्धानवे प्रतिशत से अधिक आउटपुट कर के लिए अपने दायित्व के निर्वहन हेतु इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का प्रयोग नहीं करेगा जहां छूट प्रदाय तथा शून्य-दर प्रदाय से भिन्न कराधेय प्रदाय का मूल्य एक मास में पचास लाख रुपये से अधिक है।

परंतु उक्त प्रतिबंध वहां लागू नहीं होगा जहां-

- (क) उक्त व्यक्ति अथवा स्वामी अथवा कर्ता अथवा प्रबंध निदेशक अथवा इसके दो भागीदारों में से कोई एक, पूर्णकालिक निदेशक, संगमों की प्रबंध समिति के सदस्य अथवा बोर्ड न्यासियों, जैसी भी स्थिति हो, ने पूर्व दो वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43) के अधीन आय के रूप में एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया है जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी दायर करने की समय सीमा समाप्त हो गयी है; अथवा
- (ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के खण्ड (i) के अधीन अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के कारण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक की प्रतिदाय राशि प्राप्त की है; अथवा
- (ग) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के खण्ड (ii) के अधीन अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के कारण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक की प्रतिदाय राशि प्राप्त की है; अथवा
- (घ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उस राशि के लिए इलैक्ट्रॉनिक नकद लेजर के माध्यम से आउटपुट कर के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन किया है जो चालू वित्तीय वर्ष में उक्त मास तक संचयी रूप से प्रयुक्त कुल आउटपुट कर दायित्व के एक प्रतिशत से अधिक है; अथवा
- (ङ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति-
  - (i) सरकारी विभाग; अथवा
  - (ii) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम; अथवा
  - (iii) स्थानीय प्राधिकरण; अथवा
  - (iv) सांविधिक निकाय है:

परंतु यह और कि आयुक्त अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे सत्यापनों तथा ऐसे रक्षोपायों जो वह उचित समझे, के बाद उक्त प्रतिबंध को हटा सकता है।"

10. उक्त नियमों में, नियम 138 में, उपनियम (10) में, सारणी में, खाना (2) के नीचे, प्रथम जनवरी, 2021 से -

- (क) क्रम संख्या 1 के सामने, "100 किलोमीटर" अंकों तथा शब्द के स्थान पर, "200 किलोमीटर" अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (ख) क्रम संख्या 2 के सामने, "100 किलोमीटर" अंकों तथा शब्द के स्थान पर, "200 किलोमीटर" अंक तथा शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

11. उक्त नियमों में, नियम 138ड में,-

- I. खण्ड (ख) में, "दो मास" शब्दों के स्थान पर, "दो कर अवधि" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- II. खण्ड (ग) में, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-
  - (i) अंत में विद्यमान ":" चिह्न के स्थान पर, "; या" चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
  - (ii) निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा; अर्थात् :-

"(घ) व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण नियम 21(क) के उपनियम (1) अथवा उपनियम (2) अथवा उपनियम (2क) के उपबन्धों के अधीन निलंबित कर दिया गया है:"।

12. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-30 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

## “प्ररूप जीएसटी आरईजी-31

[देखिये नियम 21क]

संदर्भ संख्या

सेवा में,

जीएसटीआरईएन:

नाम:

पता:

तिथि: &lt;दिन&gt;&lt;मास&gt;&lt;वर्ष&gt;

रजिस्ट्रीकरण के निलम्बन के लिए सूचना और रद्दीकरण के लिए नोटिस

निम्नलिखित अर्थात्,

- (i) माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 39 के अधीन आप द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी;
- (ii) प्ररूप जीएसटीआर-1 में आप द्वारा प्रस्तुत किए गए आवक प्रदायों के ब्यौरे;
- (iii) आपके आवक प्रदायों के स्वतः जनित ब्यौरे,  
\_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक की अवधि से संबंधित;
- (iv) ..... (विनिर्दिष्ट करें)  
और अन्य उपलब्ध जानकारी की तुलना में निम्नलिखित विसंगतियों/असंगतियों का पता चला है:

☐ टिप्पणी 1☐ टिप्पणी 2☐ टिप्पणी 3

(करदाता के लिए सुसंगत मानदण्डों के आधार पर भरा जाने वाला ब्यौरा).

2. ये विसंगतियों/असंगतियों प्रथम दृष्टया हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन को दर्शित करती हैं कि यदि इनका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, तो आपके रजिस्ट्रीकरण को रद्द किये जाने के लिए दायी बनाएंगी।

3. इस बात पर विचार करते हुए कि उपर्युक्त विसंगतियों/असंगतियों इतनी गंभीर हैं और इनसे राजस्व संबंधी हित पर गंभीर खतरा पैदा हुआ है तो तात्कालिक उपाय के रूप में, आपके रजिस्ट्रीकरण को नियम 21क के उपनियम (2क) के अनुसार इस सूचना की तिथि से रद्द कर दिया जाता है।

4. आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से सात कार्य दिवस के भीतर अधिकारिता रखने वाले कर अधिकारी के पास उपरोक्त कथित विसंगति/असंगति के बारे में अपना स्पष्टीकरण देते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत कर दें जीएसटी सामान्य पोर्टल पर, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी रीति में आपके प्रत्यय पत्रों का संभाव्य/दुरुपयोग अधिकार क्षेत्र वाले अधिकारी की जानकारी में विशेष रूप से लाया जा सकता है।

5. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों के साथ-साथ आपके उत्तर सहित अधिकारिता रखने वाले अधिकारी की संतुष्टि तथा किसी अन्य और सत्यापन, जो अधिकारिता रखने वाला अधिकारी उचित समझे, पर आपके रजिस्ट्रीकरण के निलम्बन को हटाया जा सकता है।

6. आप कृपया यह नोट कर लें कि आपके रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जा सकता है यदि आप विहित अवधि के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं या कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं।”।

अनुराग रस्तोगी,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**  
**Notification**

The 22nd January, 2021

**No. 03/GST-2.**— In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2021.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force from 22nd day of December, 2020.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, for sub-rule (4A), with effect from a date to be notified, the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(4A) Every application made under rule (4) shall be followed by—

- (a) biometric-based Aadhaar authentication and taking photograph, unless exempted under sub-section (6D) of section 25, if he has opted for authentication of Aadhaar number; or
- (b) taking biometric information, photograph and verification of such other KYC documents, as notified, unless the applicant is exempted under sub-section (6D) of section 25, if he has opted not to get Aadhaar authentication done,

of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under sub-section (6C) of section 25 where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in **FORM GST REG-01** at one of the Facilitation Centres notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule and the application shall be deemed to be complete only after completion of the process laid down under this sub-rule.”.

3. In the said rules, in rule 9,-

(a) in sub-rule (1), -

- (i) after the words “applicant within a period of ”, for the word “three”, the word “seven” shall be substituted;
- (ii) for **the existing provisos**, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that where-

- (a) a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number; or
- (b) the proper officer, with the approval of an officer authorised by the Commissioner not below the rank of **Deputy Commissioner of State Tax**, deems it fit to carry out physical verification of places of business,

the registration shall be granted within thirty days of submission of application, after physical verification of the place of business in the presence of the said person, in the manner provided under rule 25 and verification of such documents as the proper officer may deem fit.”;

(b) in sub-rule (2), -

- (i) for the word “three”, the word “seven” shall be substituted;
- (ii) for **the existing provisos**, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that where-

- (a) a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number; or
- (b) the proper officer, with the approval of an officer authorised by the Commissioner not below the rank of **Deputy Commissioner of State Tax**, deems it fit to carry out physical verification of places of business,

the notice in **FORM GST REG-03** may be issued not later than thirty days from the date of submission of the application.”;

- (c) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(5) If the proper officer fails to take any action, -

- (a) within a period of seven working days from the date of submission of the application in cases where the person is not covered under proviso to sub-rule (1); or
- (b) within a period of thirty days from the date of submission of the application in cases where a person is covered under proviso to sub-rule (1); or
- (c) within a period of seven working days from the date of the receipt of the clarification, information or documents furnished by the applicant under sub-rule (2),

the application for grant of registration shall be deemed to have been approved.”.

4. In the said rules, in rule 21,-
  - (a) in clause (b), after the words “goods or services”, the words “or both” shall be inserted;
  - (b) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:-
    - “(e) avails input tax credit in violation of the provisions of section 16 of the Act or the rules made thereunder; or
    - (f) furnishes the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** under section 37 for one or more tax periods which is in excess of the outward supplies declared by him in his valid return under section 39 for the said tax periods; or
    - (g) violates the provision of rule 86B.”.
5. In the said rules, in rule 21A,-
  - (a) in sub-rule (2), the words “,after affording the said person a reasonable opportunity of being heard,” shall be omitted;
  - (b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
 

“(2A) Where, a comparison of the returns furnished by a registered person under section 39 with

    - (a) the details of outward supplies furnished in **FORM GSTR-1**; or
    - (b) the details of inward supplies derived based on the details of outward supplies furnished by his suppliers in their **FORM GSTR-1**,

or such other analysis, as may be carried out on the recommendations of the Council, show that there are significant differences or anomalies indicating contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder, leading to cancellation of registration of the said person, his registration shall be suspended and the said person shall be intimated in **FORM GST REG-31**, electronically, on the common portal, or by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said differences and anomalies and asking him to explain, within a period of thirty days, as to why his registration shall not be cancelled.”;
  - (c) in sub-rule (3), after the words, brackets and figure “or sub-rule (2)”, the words, brackets, figure and letter “or sub-rule (2A)” shall be inserted;
  - (d) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
 

“(3A) A registered person, whose registration has been suspended under sub-rule (2) or sub-rule (2A), shall not be granted any refund under section 54, during the period of suspension of his registration.”;
  - (e) in sub-rule (4), -
    - (i) after the words, brackets and figure “or sub-rule (2)”, the words, brackets, figure and letter “or sub-rule (2A)” shall be inserted;
    - (ii) for “.” sign existing at the end, “.” sign shall be substituted;
    - (iii) the following proviso shall be inserted, namely: -
 

“Provided that the suspension of registration under this rule may be revoked by the proper officer, anytime during the pendency of the proceedings for cancellation, if he deems fit.”.
6. In the said rules, in rule 22,-
  - (a) in sub-rule (3), after the words, brackets and figure “the show cause issued under sub-rule (1)”, the words, brackets, figures and letters “or under sub-rule (2A) of rule 21A” shall be inserted;
  - (b) in sub-rule (4), after the words, brackets and figure “reply furnished under sub-rule (2)”, the words, brackets, figures and letters “or in response to the notice issued under sub-rule (2A) of rule 21A” shall be inserted.
7. In the said rules, in rule 36, in sub-rule (4), with effect from the 1st day of January, 2021,-
  - (a) for the word “uploaded”, at both the places where it occurs, the word “furnished” shall be substituted;
  - (b) after the words, brackets and figures “by the suppliers under sub-section (1) of section 37”, at both the places where they occur, the words, letters and figure “in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility” shall be inserted;
  - (c) for the figures and words “10 per cent.”, the figure and words “5 per cent.” shall be substituted.

8. In the said rules, in rule 59, after sub-rule (4), for the period up to 31st days of December, 2020 the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(5) Notwithstanding anything contained in this rule, -

- (a) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1**, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding two months;
- (b) a registered person, required to furnish return for every quarter under the proviso to sub-section (1) of section 39, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding tax period;
- (c) a registered person, who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of ninety-nine per cent. of such tax liability under rule 86B, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding tax period.”.

9. In the said rules, after rule 86A, with effect from the 1st day of January, 2021, the following rule shall be inserted, namely: -

“**86B. Restrictions on use of amount available in electronic credit ledger.**-Notwithstanding anything contained in these rules, the registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of ninety-nine percent of such tax liability, in cases where the value of taxable supply other than exempt supply and zero-rated supply, in a month exceeds fifty lakh rupees:

Provided that the said restriction shall not apply where -

- (a) the said person or the proprietor or karta or the managing director or any of its two partners, whole-time Directors, Members of Managing Committee of Associations or Board of Trustees, as the case may be, have paid more than one lakh rupees as income tax under the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) in each of the last two financial years for which the time limit to file return of income under subsection (1) of section 139 of the said Act has expired; or
- (b) the registered person has received a refund amount of more than one lakh rupees in the preceding financial year on account of unutilised input tax credit under clause (i) of first proviso of sub-section (3) of section 54; or
- (c) the registered person has received a refund amount of more than one lakh rupees in the preceding financial year on account of unutilised input tax credit under clause (ii) of first proviso of sub-section (3) of section 54; or
- (d) the registered person has discharged his liability towards output tax through the electronic cash ledger for an amount which is in excess of 1% of the total output tax liability, applied cumulatively, upto the said month in the current financial year; or
- (e) the registered person is -
  - (i) Government Department; or
  - (ii) a Public Sector Undertaking; or
  - (iii) a local authority; or
  - (iv) a statutory body:

Provided further that the Commissioner or an officer authorised by him in this behalf may remove the said restriction after such verifications and such safeguards as he may deem fit.”.

10. In the said rules, in rule 138, in sub-rule (10), with effect from the 1st day of January, 2021,-

- (a) in the Table, against serial number 1, in column 2, for the figures and letters “100 km.”, the figures and letters “200 km.” shall be substituted;
- (b) in the Table, against serial number 2, in column 2, for the figures and letters “100 km.”, the figures and letters “200 km.” shall be substituted.

11. In the said rules, in rule 138E, -

- I. in clause (b), for the words “two months”, the words “two tax periods” shall be substituted;
- II. (i) for “:” sign existing at the end, the “; or” sign and word shall be substituted;
- (ii) the following clause shall be inserted, namely :-

“(d) being a person, whose registration has been suspended under the provisions of sub-rule (1) or sub-rule (2) or sub-rule (2A) of rule 21A.”.

12. In the said rules, after **FORM GST REG-30**, the following **FORM** shall be inserted, namely-



**“FORM GST REG – 31***[See rule 21A]*

Reference No.

Date: &lt;DD&gt;&lt;MM&gt;&lt;YYYY&gt;

To,

GSTIN

Name:

Address:

**Intimation for suspension and notice for cancellation of registration**

In a comparison of the following, namely,

- (i) returns furnished by you under section 39 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017;
- (ii) outwards supplies details furnished by you in **FORM GSTR-1**;
- (iii) auto-generated details of your inwards supplies  
for the period \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_;
- (iv) ..... (specify)

and other available information, the following discrepancies/ anomalies have been revealed:

- ☐ Observation 1
- ☐ Observation 2
- ☐ Observation 3

*(details to be filled based on the criteria relevant for the taxpayer).*

2. These discrepancies/anomalies prima facie indicate contravention of the provisions of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder, such that if not explained satisfactorily, shall make your registration liable to be cancelled.
3. Considering that the above discrepancies/anomalies are grave and pose a serious threat to interest of revenue, as an immediate measure, your registration stands suspended, with effect from the date of this communication, in terms of sub-rule (2A) of rule 21 A.
4. You are requested to submit a reply to the jurisdictional tax officer within seven working days from the receipt of this notice, providing explanation to the above stated discrepancy/ anomaly. Any possible misuse of your credentials on GST common portal, by any person, in any manner, may also be specifically brought to the notice of jurisdictional officer.
5. The suspension of registration shall be lifted on satisfaction of the jurisdictional officer with the reply along with documents furnished by you, and any further verification as jurisdictional officer considers necessary.
6. You may please note that your registration may be cancelled in case you fail to furnish a reply within the prescribed period or do not furnish a satisfactory reply.

ANURAG RASTOGI,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.